केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिए मकान आरक्षित करना

*666. **श्री मोलहू प्रसाद :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को सवर्ण हिन्दुओं से किराये पर मकान लेने के मामलों से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी अन्य जातियों के कर्मचारियों की तुलना में सेवाओं में बाद में आये हैं और वरिष्ठता के आधार पर उन्हें 20 से 25 वर्ष बाद ही मकान मिल सकेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये मकान आरक्षित करने का है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING, AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) The Scheduled Castes Welfare Organisation of India had represented that Scheduled Castes Government employee find difficulty in getting houses, on rent, from caste Hindus.

(b) Though there is no provision in the application forms for residential accommodation about the castes and creeds of the applicants and as such no specific statistical date is available in the Directorate of Estates on this point, it is true that the employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes must be late in seniority ;

(c) Government find it difficult to reserve general pool accommodation on the basis on caste and creed.

श्री मोलहू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस सरकार के सामने हर चीज की कठिनाई है - मंत्रि मंडल में आरक्षण को पूरा करने में कठिनाई है, राज्यपालों की नियुक्ति में कठिनाई है, राजदूतों में आरक्षण करने में कठिनाई है और केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों में आरक्षण को पूरा करने में कठिनाई है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया है कि जब वे लोग नौकरी में ही 20-25 वर्ष बाद आये हैं तो फिर उनको टर्न के आधार पर क्वार्टर भी 20-25 वर्ष के बाद ही मिलेगा तो फिर वे इस वक्त कहां रहेंगे जबकि खुले मार्केट में उनके लिए मकान मिलना असम्भव है ? सरकार इस बात पर विचार क्यों नहीं करती है ? तमाम कमेटियां बनाई जाती हैं जिनकी रपट रद्दी की टोकरी में चली जाती है । इस पर विचार क्यों नहीं होता ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI K. K. SHAH) : It is a difficult question This question has been considered four times : it was considered in 1960, it was again considered in 1961, it was again considered in 1965, again in 1968, but unluckily..

AN HON. MEMBER : But brought forth nothing.

SHRI K. K. SHAH : If the hon. members bear with me ,then they will be able to share the difficulties with me. We have not got sufficient accommodation. First of all, we have not been able to reach, in some cases, even persons who have been appointed in 1949, persons who have been appointed in 1940, persons who have been appointed in 1944... .... *(Interruptions)*

AN HON. MEMBER : Scheduled Castes.

SHRI K. K. SHAH : All classes. Even if

I make some reservation, juniors will have to be given preference over seniors.. (*Interruptions*) I am prepared to consider everything. I want your assistance. If juniors get preference over seniors, it will create heart-burning. So, all these things considered and it was thought that the only way to meet them was to give them preference in out-of-turn allotment. By granting them out-of-turn allotment, the demand on medical grounds has been so much that today I have got more than 900 cases, allotted on the basis of out-of-turn allotment, which I am not able to meet. This is the difficult situation.

श्री मोलहू प्रसाद : अभी इसी प्रश्न की सफाई नहीं हुई। मन्त्री जी कह रहे हैं कि आवेदन-पत्र तमाम आये हैं। तो आवेदन-पत्र जितने आयेंगे उतना आप कब तक पूरा कर लेंगे इसका कुछ अन्दाजा नहीं है और यह अन्दाजा इसलिए नहीं है कि आप एयर कण्डीशन्ड भवन बनाने में लगे हुए हैं, छोटे-छोटे क्वार्टर बनाकर सारे कर्मचारियों की समस्या हल करने के लिए तैयार नहीं है। अफसरों के मकानों की व्यवस्था आप अधिक कर रहे हैं और ये अफसर एयर कन्डीशन्ड कमरों में बैठकर सारी स्कीम बनाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनको स्वास्थ्य और आउट आफ टर्न के आधार पर जो क्वार्टर अलाट कर रहे हैं, इसके अलावा कौन सा दूसरा वैकल्पिक उपाय आपके सामने है जो अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को क्वार्टर दिलाने में सफलता प्राप्त करेंगे ?

श्री के० के० शाह : क्लास एक के जो सब से छोटे क्वार्टर हैं इसमें हम कोशिश करके 1955 तक पहुँचे हैं, औरों में इतना नहीं पहुँचे हैं। इससे आपको स्पष्ट होगा कि एयर कण्डीशन की ज्यादा कोशिश नहीं की। और क्लास चार, पांच और छः में कोशिश करके आगे जाने की कोशिश की है। औरों में कोशिश करके पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह सही बात है कि दिल्ली में अकेले 50,000 गवर्नमेंट सर्वेन्टस् को अभी तक क्वार्टर नहीं दे पाये हैं।

श्री बलराज मधोक : सबसे पहले तो इस प्रश्न के अन्दर जो इन्सीनुएशन है कि दिल्ली के अन्दर कास्ट हिन्दू मकान नहीं देते, मैं इसका खंडन करना चाहता हूं। दिल्ली के लैण्ड लार्डस् का प्रीफरेंस है कि वह पहले मकान देंगे साउथ इण्डियन को या गुजराती को। नार्थ इण्डियन को मकान देने में वह आनाकानी करते हैं।

AN HON. MEMBER : They pay rent in time. That is why they are preferred.

SHRI SONAVANE : Is the Jan Sangh leader prepared to give residential quarter to the Harijans ? Let him come with me and do it.

श्री बलराज मधोक : इसलिये यह कहना कि शेड्यूल कास्ट वालों को नहीं देते हैं, यह गलत है।...

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI : In view of the fact that the hon. Minister has stated that housing difficulty is there for the scheduled castes and scheduled tribes, I want to ask this. The Constitution has provided for special representation even for representation of these people in the State legislatures and in the Parliament. Even then, some kind of priority will have to be givin so that this question will be solved and we should not put obstacle or obstruction in the way. So, I want to know this. Is the hon. Minister prepared to find out some means of giving special priority in view of the fact that these scheduled castes and scheduled tribes people do not get accommodation with caste Hindus and their accommodation diffieulty is very real ?

SHRI K. K. SHAH : I am prepared to take the help of leaders of political parties in this matter and I am prepared to work on those lines.

श्री बलराज मधोक : किसी समय अक्ल की बात भी किया करो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य है कि दिल्ली के अन्दर सरकारी कर्मचारियों के मकानों की संख्या बहुत कम है। इस हाउस में बार-बार आवाज उठाने के बावजूद भी यह काम नहीं किया गया। यहां पर रिवालविंग टावर के लिए एक करोड़ रुपया

निकाल लिया, प्रधान मन्त्री के मकान के लिए 10 लाख निकाल रहे हैं, मगर गरीब कर्मचारियों के लिए रुपया नहीं निकाल सकते। मेरा कहना है कि जो प्रधान मन्त्री के मकान के लिये रुपया है उस सब को कैन्सिल करके कर्मचारियों के लिए पहले मकान बनायेंगे तो आपके जितने दिल्ली में कर्मचारी हैं सबको मकान मिल सकेगा। क्या ऐसा आप करने को तैयार हैं ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह तथ्य है कि आउट आफ टर्न के नाम पर सिफारशी लोगों को मकान मिल जाते हैं और जो कर्मचारी 20, 20 साल से पडे हुए हैं उनको मकान अभी तक नहीं मिल रहा है। इसके बारे में जांच करके आप बतायेंगे ताकि सिफारिशी अलाटमेंट बन्द हो।

और तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या यह तथ्य है कि वेस्टर्न दिल्ली में टैगोर गार्डन के पास लगभग 300 क्वार्टर जो हरिजन भाइयों के लिए बनाए गए है उन को तैयार हुए डेढ़, दो साल हो गया है, लेकिन अभी तक अलाट नहीं किए गए हैं। उस का क्या कारण है मंत्री जी जवाब दें ?

श्री के० के० शाह : दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ कि मैंने आउट आफ टर्न अलाटमेंट बन्द कर दिया क्योंकि आज तक जितने आउट आफ टर्न अलाटमेंट्स इसके पहले हुए हैं उसी को पूरा कराने में शायद सात से दस साल लगेंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आउट आफ टर्न आगे नहीं लेंगे, इसी को पूरा करेंगे ?

श्री के० के० शाह : 10 परसेंट के बजाय साढ़े बारह परसेंट आउट आफ टर्न अलाटमेंट कर दिया गया और जितने आर्डर किये हैं उन्हीं को सात साल में पूरा नहीं कर सकते हैं। इस लिए मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूं अगर पैसा ज्यादा मिले तो इस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मधोक साहब को पता है, बात भी की है, यहां पर कितनी कोशिश हो रही है, मकान कितने बने हैं और अनअथौराइज्ड.....

श्री मधु लिमये : इस लिए मन्त्री जी पतले हो गये हैं।

श्री के० के० शाह : यह सही बात है।

MR. SPEAKER : If the hon. Minister answers through the Chair, then there would be no difficulty. He seems to agree with everything that the Opposition leaders are saying. That is why there are so many interruptions.

SHRI K. K. SHAH : It is a difficult task. Along with unauthorised occupation on one side, I have to deal with the unauthorised occupants for whom plots have to be found and buildings have to be constructed, and crores of rupees have been spent on that. For Government servants also, crores of rupees have been spent. What greater demonstration of it can be given than the number of colonies which have sprung up ? It is true that there is paucity of funds and we have not been able to do as much as we can.

SHRI RANGA : Don't waste money on a new bungalow for the Prime Minister.

SHRI BAL RAJ MADHOK : Will he divert the funds that he has allotted for the Prime Minister's house and other such things which could wait ? Is he prepared to divert those funds for constructing houses for Government servant's ? He can get enough funds from this for that purpose.

SHRI K. K. SHAH : That way, a number of questions can be asked. For instance, the question can be asked whether the Vithal Bhai Patel House should have been constructed or not, ...(*Interruptions*)

श्री रवि राय : वह तो बन चुका है। नया मकान नहीं बनाना है। 10 लाख रु० से प्रधान मन्त्री का मकान नहीं बनाना है।

MR. SPEAKER : Without getting into arguments, he may say 'Yes' or 'No'.

SHRI K. K. SHAH : No, it is not necessary; we can find the amount otherwise also.

SHRI BAL RAJ MADHOK : What about the allotment of houses in Tagore Gardens ? There are about 300 houses there waiting for allotment for two years.

SHRI K. K. SHAH : I shall examine it.

SHRI BASUMATARI : It is evident that there is some mental reservation inside and outside and also in the reply given by the hon. Minister. The purpose of the question is this. At present, the allotment is based on seniority of service, but the Scheduled Castes and Scheduled Tribes being appointed only two to three years before in services would not be able to getany allotment ont hat basis. May I know whether special consideration would be shown to them as a matter of policy and whether such circulars will be sent to all Departments by the Home Minister or by the hon. Minister in charge of Housing ?

SHRI K. K. SHAH : As I have said, I am prepared to take the advice of our friends, but the difficulty will be when we give to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, there will be others also who will have to be considered; it is not such an easy question that we can find a solution quickly, but I am prepared to give it a second thought.

श्री एस० एम० जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बहुत गम्भीर है। हम लोगों को मान लेना चाहिए कि हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके बारे में आपने अभी तक पूरा न्याय नहीं किया है, और जो मकानात की कमी है उसके कारण उन लोगों को तकलीफ होती है। हमारे मधोक साहब नाराज हो गये, दिल्ली में न हों, मगर दूसरी जगह ऐसा है कि कास्ट हिन्दू शेड्यूल कास्ट को मकान देने के लिए उतने राजी नहीं रहते। सवाल यह है कि जब हाउसिंग बोर्ड वगैरह आपके क्वार्टर बनाते हैं तो जहां नौकरियों में शेड्यूल्ड कास्ट्स लोगों के लिए सुरक्षित स्थान रखते हैं, ऐसे ही जहां उन को मकान नहीं मिलता है वहां भी उनके संरक्षण की बहुत जरूरत है। ऐसी हालत में हमारे मन्त्री महोदय ने बताया कि बहुत जमाने से आवेदन पत्र पड़े हुए हैं उनका फैसला नहीं किया, तो इस हिसाब से तो उनको अगले जन्म में भी मकान नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरा सवाल यह है कि मन्त्री महोदय ने कहा कि विरोधी लोगों के सहयोग से हम कुछ करना चाहते हैं। तो मैं मन्त्री महोदय से यह सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर विरोधी दल के नेता लोग और आप लोग बैठ कर कोई फैसला करेंगे तो उसके ऊपर अमल करने के लिए हुकूमत तैयार है?

श्री के० के० शाह : नहीं तो मैं आपको पूछूंगा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मन्त्री महोदय ने दो दिक्कतें बतायी है, पहली यह है कि 1949 तक के लोगों को अभी तक मकान नहीं मिला है। नम्बर दो उन्होंने यह कहा कि अगर हरिजनों के मकान के लिए किसी प्रकार का संरक्षण होगा तो लोगों के अन्दर एक ईर्षा और द्वेष की भावना पैदा होगी इसी लिए मकानों के मामले में संरक्षण करने में कठिनाई हो रही है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समाज में और सारे देश में यह बात है, इसमें दिल्ली भी शामिल है, आम तौर से लोगों के अन्दर एक भावना है वह हरिजनों और मुसलमानों को मकान देने में आनाकानी करते हैं, उनको देना नहीं चाहते। आज देश और समाज के अन्दर जो हरिजनों की दशा है उसको ध्यान में रखते हुए हरिजनों के जो लड़के सरकारी नौकरी में आये हैं सन् 47 के बाद आमतौर से उनको नौकरी आदि के मामले में संरक्षण दिया गया है। संविधान सभा ने इस सदन के अन्दर और देश के सारे विधान मण्डलों के अन्दर हरिजनों को नौकरियां आदि के मामले में संरक्षण देने के हेतु कानून में व्यवस्था की थी। अब प्रश्न यह है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैडल्ड ट्राइब्स के सरकारी कर्मचारियों को रहने के लिए मकान आदि नहीं मिलते हैं तो क्या सरकार

इस बात को विचार में रखते हुए कि उन्हें आवास की काफी कठिनाई प्रतीत हो रही है तमाम राजनैतिक दलों की बैठक बुला कर एक सर्वसम्मत फैसले पर पहुंचेगी ताकि जो नये मकानात बन रहे हैं उनमें इन हरिजन सरकारी नोकरियों के लिए कुछ प्रतिशत रिजर्व किया जा सके ?

दूसरे और भी जो संस्थाएं है, लोकल सेल्फ गवर्नमैंट बौडीज़ हैं वह भी अपने वहां मकान के मामले में हरिजन कर्मचारियों को आरक्षण दें क्या सरकार इस बात का भी ध्यान रखेगी ?

SHRI K. K. SHAH : I have answered it already.

श्री स० मो० बनर्जी : चूंकि क्वाटरों की कमी है और खास तौर से हरिजन सरकारी कर्मचारियों को मकान मिलते नहीं हैं तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस चीज का इन्तजाम करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इस बिड़ला भवन को एक्वायर करके वहां हरिजनों के वास्ते क्वाटर्स बना दें ? गांधी जी जीवनपर्यन्त हरिजनों की बेहतरी और उनकी तमाम समस्याओं के हल के लिए प्रयत्नशील रहे तो क्या सरकार द्वारा गांधीजी के नाम पर हरिजन कर्मचारियों के आवास की समस्या को हल करने के लिए बिड़ला भवन ऐक्वायर किया जायेगा ?

MR. SPEAKER : Shri Sonavane.

SHRI S. M. BANERJEE : Is it being acquired or not ? Let him answer that portion.

MR. SPEAKER : That is a different question. The main question here relates to accommodation for Harijans.

SHRI SONAVANE : May I know whether the hon. Minister has projected the mind of the officials or he has projected the mind of the Congress Minister who is a disciple of Gandhiji who cared so much for Harijans and their welfare ?

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : The hon. Minister has just now told us that he has received applications for out-of-turn allotment which if he wants to fulfil it will take about seven years. May I know whether he has stopped allotting out-of-turn accommodation altogether or he will take seven years to fulfil the out-of-turn demands or applications which are there now and then stop it ?

SHRI K. K. SHAH : I have stopped out-of-turn allotment completely.

MR. SPEAKER : Next question.

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, नये मेम्बरों को तो कम से कम चांस देना ही चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत लोगों को चांस दिया गया है ।

श्री सूरज भान : यह हरिजनों का सवाल है इसलिए हरिजन मेम्बरों को तो खास तौर से आपको चांस देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । मैं ने अगला सवाल बुला लिया है ।

श्री सूरज भान : हरिजनो की जो बात कहना चाहते हैं उसको बोलने ही नही देते हैं और इस बारे में मेरा प्रोटेस्ट है । एक मिनट की इजाजत मुझे नहीं दी जा रही है लेकिन जो शोर मचाते हैं उनको यहां पर चांस मिल जाता है ।

MR. SPEAKER : I am notg oing to allow him now. I have already gone over to the next question. If he wants to shout, he may do whatever he likes..............After all, his leader has asked a question. If he wants a Scheduled Caste leader, then sixty or seventy of them may join together and elect a Scheduled Caste leader. Now, next question.